

NT>

Title: Regarding fixing the minimum support price of sugarcane in Uttar Pradesh.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसान इस बात से परेशान हैं कि गन्ने का रेट तय नहीं किया जा रहा है। अखबार में इस बात की खबर छपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेश को मिसइण्टरप्रेट करके उत्तर प्रदेश की सरकार को बरगलाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राजाज्ञा जारी की थी, उस राजाज्ञा को वापस करा लिया गया। इसके अन्दर उद्योगपतियों की और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों की सीधे-सीधे साजिश पता लग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उनकी मिली-जुली साजिश है। उच्चतम न्यायालय के केवल आधे आदेश को, जो उसका अन्तरिम आदेश था, उसके आधार पर प्लीड किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी राजाज्ञा वापस ले ली। परन्तु 31 जनवरी, 2001 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि राज्य सरकारों को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का पूरा-पूरा अख्तियार है। इस विषय पर उत्तर प्रदेश के काश्तकारों के अधिकारों को बेच दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे और उत्तर प्रदेश के करोड़ों गन्ना किसानों की जिंदगी को बचाने के लिए कोशिश करे।